भारतीय राजनीति : नए बदलाव

In this chapter...

In this last chapter we take a synoptic view of the last two decades of politics in India. These developments are complex, for various kinds of factors came together to produce unanticipated outcomes in this period.

इस अध्याय में...

इस अध्याय में हम पिछले दो दशकों की भारतीय राजनीति का एक संक्षिप्त जायजा लेंगे। इस अविध में कुछ जिटल किस्म के बदलाव आए। कई कारकों ने एक साथ मिलकर इस अविध में अप्रत्याशित परिणाम दिए।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

The new era in politics was impossible to foresee; it is still very difficult to understand. These developments are also controversial, for these involve deep conflicts and we are still too close to the events. Yet we can ask some questions central to the political change in this period.

राजनीति के इस नए दौर का पूर्वानुमान कर पाना असंभव था और अब भी इसे समझना बहुत कठिन है। इस दौर के बदलाव बडे विवादास्पद हैं, क्योंकि इनके साथ संघर्ष के कुछ गहरे मसले जुडे हुए हैं और हम सब अभी इन बदलावों से इतने दूर नहीं जा पाए हैं कि इनके स्वरूप को साफ-साफ परख सकें। बहरहाल इस दौर के राजनीतिक बदलावों को लेकर हम कुछ बुनियादी सवाल कर सकते हैं:

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

- What are the implications of the rise of coalition politics for our democracy?
- What is Mandalisation all about? In which ways will it change the nature of political representation?
- What is the legacy of the Ramjanambhoomi movement and the Ayodhya demolition for the nature of political mobilisation?
- What does the rise of a new policy consensus do to the nature of political choices?

- ■गठबंधन की राजनीति के उदय का हमारे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ा है?
- ■मंडलीकरण क्या है? इसने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के स्वभाव को किन रूपों में बदला है?
- ■राजनीतिक लामबंदी के लिहाज़ से रामजन्मभूमि आंदोलन और बाबरी मस्ज़िद विध्वंस ने क्या विरासत छोड़ी है?
- ■नीतिगत मामलों पर एक सर्व–सहमित सी बन गई है—इसका राजनीतिक विकल्पों के चयन के लिहाज़ से क्या असर हुआ है?

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

The chapter does not answer these questions. It simply gives you the necessary information and some tools so that you can ask and answer these questions when you are through with this book. We cannot avoid asking these questions just because they are politically sensitive, for the whole point of studying the history of politics in India since Independence is to make sense of our present.

यह अध्याय इन सवालों के जवाब नहीं देता। इस अध्याय में आपको कुछ जरूरी सूचनाएँ दी गई हैं और कुछ तरीके बताए गए हैं, ताकि जब आप इस किताब को आखिर तक पढ़ लें, तो आप ये सवाल पूछ सकें और इनके जवाब तलाश सकें। ये सवाल राजनीतिक लिहाज से संवेदनशील हैं. लेकिन मात्र इसी कारण से हम इन सवालों को पूछने से बच नहीं सकते। आजादी के बाद की भारतीय राजनीति के इतिहास को आखिर पढ़ने का मकसद ही यही है कि हम अपने वर्तमान को समझ सकें।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

Cont the 1990s

You have read in the last chapter that Rajiv Gandhi became the Prime Minister after the assassination of Indira Gandhi. He led the Congress to a massive victory in the Lok held Sabha elections immediately thereafter in 1984. As the decade of the eighties came to a close, the country witnessed five developments that were to make a longlasting impact on our politics.

1990 का दशक

आपने पिछले अध्याय में पढा था कि इंदिरा गाँधी की हत्या के बाद राजीव गाँधी प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गाँधी की हत्या के कुछ दिनों बाद ही 1984 में लोकसभा के चुनाव हुए। राजीव गाँधी की अगुवाई में कांग्रेस को इस चुनाव में भारी विजय मिली। 1980 के दशक के आखिर के सालों में देश में एसे पाँच बड़े बदलाव आए. जिनका हमारी आगे की राजनीति पर गहरा असर पड़ा।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

First the most crucial development of this period was the defeat of the **Congress party in the** elections held in 1989. The party that had won as many as 415 seats in the Lok Sabha in 1984 was reduced to only 197 in this election. The Congress improved its performance and came back to power soon after the midterm elections held in 1991.

पहला, इस दौर की एक महत्त्वपूर्ण घटना 1989 के चुनावों में कांग्रेस की हार है। जिस पार्टी ने 1984 में लोकसभा की 415 सीटें जीती थीं वह इस चुनाव में महज 197 सीटें ही जीत सकी। 1991 में एक बार फिर मध्याविध चुनाव हुए और कांग्रेस इस बार अपना आँकड़ा सुधारते हुए सत्ता में आयी।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

But the elections of 1989 marked the end of what political scientists have called the 'Congress system'. To be sure, the Congress remained an important party and ruled the country more than any other party even in this period since 1989. But it lost the kind of centrality it earlier enjoyed in the party system.

बहरहाल. 1989 में ही उस परिघटना की समाप्ति हो गई थी. जिसे राजनीति विज्ञानी अपनी खास शब्दावली में 'कांग्रेस प्रणाली' कहते हैं। यह बात तो प्रकट ही है कि कांग्रेस एक महत्त्वपूर्ण पार्टी के रूप में कायम रही और 1989 के बाद भी देश पर किसी अन्य पार्टी के बजाय उसका शासन ज्यादा दिनों तक रहा। लेकिन. दलीय प्रणाली के भीतर जैसी प्रमुखता इसे पहले के दिनों में हासिल थी. वैसी अब न रही।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

Second development was the rise of the 'Mandal issue' in national politics. This followed the decision by the new National Front government in 1990, to implement the recommendation of the **Mandal Commission that** jobs in central government should be reserved for the Other Backward Classes.

दूसरा बड़ा बदलाव राष्ट्रीय राजनीति में 'मंडल मुद्दे' का उदय था। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की नयी सरकार ने मंडल आयोग की सिफ़ारिशों को लागू किया। इन सिफ़ारिशों के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार की नौकरियों में 'अन्य पिछड़ा वर्ग' को आरक्षण दिया जाएगा।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

This led to violent 'antiMandal' protests in different parts of the country. This dispute between the supporters and opponents of OBC reservations was known as the 'Mandal issue' and was to play an important role in shaping politics since 1989.

सरकार के इस फ़ैसले से देश के विभिन्न भागों में मंडल-विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए। अन्य पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण के समर्थक और विरोधियों के बीच चले विवाद को 'मंडल मुद्दा' कहा जाता है। इसने 1989 के बाद की राजनीति में अहम भूमिका निभाई।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

Third, the economic policy followed by the various governments took a radically different turn. This is known as the initiation of the structural adjustment programme or the new economic reforms.

तीसरा, विभिन्न सरकारों ने इस दौर में जो आर्थिक नीतियां अपनायीं, वे बुनियादी तौर पर बदल चुकी थीं। इसे ढाँचागत समायोजन कार्यक्रम अथवा नए आर्थिक सुधार के नाम से जाना गया।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

by Rajiv Gandhi, **Started** these changes first became very visible in 1991 and radically changed the direction that the Indian economy had pursued since Independence. These policies have been widely criticised by various movements and organisations. But the various governments that came to power in this period have continued to follow these.

इनकी शुरुआत राजीव गाँधी की सरकार के समय हुई और 1991 तक ये बदलाव बड़े पैमाने पर प्रकट हुए। आज़ादी के बाद से अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था जिस दिशा में चलती आई थी, वह इन नए आर्थिक सुधारों के कारण मूलगामी अथों में बदल गई। नयी आर्थिक नीतियों की विभिन्न आंदोलनों और संगठनों की तरफ़ से भरपूर आलोचना हुई। बहरहाल इस अवधि में जितनी सरकारें बनीं. सबने नयी आर्थिक नीति पर अमल जारी रखा।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

Fourth, a number of events culminated in the demolition of the disputed structure at Ayodhya (known as Babri Masjid) in December 1992. This event symbolised and triggered various changes in the politics of the country and intensified debates about the nature of Indian nationalism and secularism. These developments are associated with the rise of the BJP and the politics of 'Hindutva'

चौथे, घटनाओं के एक सिलसिले की परिणति अयोध्या स्थित एक विवादित ढाँचे (बाबरी मस्ज़िद के रूप में प्रसिद्ध) के विध्वंस के रूप में हुई। यह घटना 1992 के दिसंबर महीने में घटी। इस घटना ने देश की राजनीति में कई परिवर्तनों को जन्म दिया और उनका प्रतीक बनी। इस घटना से भारतीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर बहस तेज हो गई।इन बदलावों का संबंध भाजपा के उदय और हिंदुत्व की राजनीति से

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

Finally, the assassination of Rajiv Gandhi in May 1991 led to a change in leadership of the Congress party. He was assassinated by a Sri Lankan Tamil linked to the LTTE when he was on an election campaign tour in Tamil Nadu. In the elections of 1991, Congress emerged as the single largest party. Following Rajiv Gandhi's death, the party chose Narsimha Rao as the Prime Minister.

इस सिलसिले की आखिरी बात यह है कि मई 1991 में राजीव गाँधी की हत्या कर दी गई और इसके परिणामस्वरूप कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ। राजीव गाँधी चुनाव अभियान के सिलसिले में तिमलनाडु के दौरे पर थे। तभी लिट्टे से जुड़े श्रीलंकाई तिमलों ने उनकी हत्या कर दी। 1991 के चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी विजयी पार्टी के रूप में सामने आयी। राजीव गाँधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री चुना।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

Era of Coalitions

Elections in 1989 led to the defeat of the Congress party but did not result in a majority for any other party. Though the Congress was the largest party in the Lok Sabha, it did not have a clear majority and therefore, it decided to sit in the opposition.

गठबंधन का य्ग

1989 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी दूसरी पार्टी को इस चुनाव में बहुमत मिल गया था। कांग्रेस अब भी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत में न होने के कारण उसने विपक्ष में बैठने का फ़ैसला किया।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

The National Front (which itself was an alliance of Janata Dal and some other regional parties) received support from two diametrically opposite political groups: the BJP and the Left Front. On this basis, the National Front formed a coalition government, but the **BJP** and the Left Front did not join in this government.

राष्ट्रीय मोर्चे को (यह मोर्चा जनता दल और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों को मिलाकर बना था) परस्पर विरुद्ध दो राजनीतिक समुहों -भाजपा और वाम मोर्चे - ने समर्थन दिया। इस समर्थन के आधार पर राष्ट्रीय मोर्चा ने एक गठबंधन सरकार बनायी. लेकिन इसमें भाजपा और वाम मोर्चे ने शिरकत नहीं की।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

Decline of Congress

The defeat of the Congress party marked the end of Congress dominance over the Indian party system. Do you remember the discussion in Chapter Five about the restoration of the Congress system?

कांग्रेस का

पतन कांग्रेस की हार के साथ भारत की दलीय व्यवस्था से उसका दबदबा खत्म हो गया। अध्याय पाँच में कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना की चर्चा की गई थी। क्या आपको यह चर्चा याद है।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

Way back in the late sixties, the dominance of the **Congress party was** challenged; but the Congress under the leadership of Indira Gandhi, managed to reestablish its predominant position in politics. The nineties saw yet another challenge to the predominant position of the Congress. It did not, however, mean the emergence of any other single party to fill in its place.

1960 के दशक के अंतिम सालों में कांग्रेस के एकछत्र राज को चुनौती मिली थी, लेकिन इंदिरा गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारतीय राजनीति पर अपना प्रभुत्व फिर से कायम किया। नब्बे के दशक में कांग्रेस की अग्रणी हैसियत को एक बार फिर चुनौती मिली। बहरहाल इसका मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस की जगह कोई दूसरी पार्टी प्रमुख हो गई।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

Thus, began an era of multiparty system. To be sure, a large number of political parties always contested elections in our country. Our Parliament always had representatives from several political parties. What happened after 1989 was the emergence of several parties in such a way that one or two parties did not get most of the votes or seats.

इस दौर में कांग्रेस के दबदबे के खात्मे के साथ बहुदलीय शासन-प्रणाली का यग शुरू हुआ। यह तो निश्चित ही है कि अपने देश में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ती आयी हैं। हमारी संसद में हमेशा कई दलों के सांसद रहे हैं। 1989 के बाद एक नयी बात देखने में आयी। अब कई पार्टियां इस तरह उभरीं कि किसी एक-दो पार्टी को ही अधिकाँश वोट या सीट नहीं मिल पाते थे।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

This also meant that no single party secured a clear majority of seats in any Lok Sabha election held since 1989 till 2014. This development initiated an era of coalition governments at the Centre, in which regional parties played a crucial role in forming ruling alliances.

इसका मतलब यह भी हुआ कि 1989 के बाद से लोकसभा के चुनावों में कभी भी किसी एक पार्टी को 2014 तक पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इस बदलाव के साथ केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ और क्षेत्रीय पार्टियों ने गठबंधन सरकार बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

Alliance politics

The nineties also saw the emergence of powerful parties and movements that represented the Dalit and backward castes (Other **Backward Classes or OBCs).** Many of these parties represented powerful regional assertion as well. These parties played an important role in the United Front government that came to power in 1996.

गठबंधन की राजनीति

नब्बे का दशक कुछ ताकतवर पार्टियों और आंदोलनों के उभार का साक्षी रहा। इन पार्टियों और आंदोलनों ने दलित तथा पिछड़े वर्ग (अन्य पिछडा वर्ग या ओबीसी) की नुमाइंदगी की। इन दलों में से अनेक ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी दमदार दावेदारी की। 1996 में बनी संयुक्त मोर्चे की सरकार में इन पार्टियों ने अहम किरदार निभाया।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

The United Front was similar to the National Front of 1989 for it included Janata Dal and several regional parties. This time the BJP did not support the government. The United Front government was supported by the Congress. This shows how unstable the political equations were.

संयुक्त मोर्चा 1989 के राष्ट्रीय मोर्चे के ही समान था. क्योंकि इसमें भी जनता दल और कई क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थीं। इस बार भाजपा ने सरकार को समर्थन नहीं दिया। संयुक्त मोर्चा की सरकार को कांग्रेस का समर्थन हासिल था। इससे पता चलता है कि राजनीतिक समीकरण किस कदर छुईमुई थे।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

In 1989, both the Left and the **BJP** supported the National **Front Government because** they wanted to keep the Congress out of power. In 1996, the Left continued to support the non-Congress government but this time the Congress, supported it, as both the Congress and the Left wanted to keep the BJP out of power.

1989 में भाजपा और वाम मोर्चा दोनों ने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को समर्थन दिया था. क्योंकि ये दोनों कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। इस बार वाममोर्चा ने गैर-कांग्रेसी सरकार को अपना समर्थन जारी रखा, लेकिन संयुक्त मोर्चा की सरकार को कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया। दरअसल. कांग्रेस और वाममोर्चा दोनों इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

They did not succeed for long, as the BJP continued to consolidate its position in the elections of 1991 and 1996. It emerged as the largest party in the 1996 election and was invited to form the government. But most other parties were opposed to its policies and therefore, the **BJP** government could not secure a majority in the Lok Sabha.

बहरहाल इन्हें ज्यादा दिनों तक सफलता नहीं मिली और भाजपा ने 1991 तथा 1996 के चुनावों में अपनी स्थिति लगातार मज़बूत की। 1996 के चुनावों में यह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस नाते भाजपा को सरकार बनाने का न्यौता मिला। लेकिन अधिकांश दल. भाजपा की नीतियों के खिलाफ थे और इस वजह से भाजपा की सरकार लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर सकी।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

It finally came to power by leading coalition government from May 1998 to June 1999 and was reelected in October 1999. Atal Behari Vajpayee was the Prime Minister during both these NDA governments and his government formed in 1999 completed its full term.

आखिरकार भाजपा एक गठबंधन (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन-राजग) के अगुआ के रूप में सत्ता में आयी और 1998 के मई से 1999 के जून तक सत्ता में रही। फिर 1999 के अक्तूबर में इस गठबंधन ने दोबारा सत्ता हासिल की। राजग की इन दोनों सरकारों में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। 1999 की राजग सरकार ने अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा किया।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

Thus, with the elections of 1989, a long phase of coalition politics began in India. Since then, there have been eleven governments at the Centre, all of which have either been coalition governments or minority governments supported by other parties, which did not join the government.

इस तरह 1989 के चुनावों से भारत में गठबंधन की राजनीति के एक लंबे दौर की शुरुआत हुई। इसके बाद से केंद्र में 11 सरकारें बनीं। ये सभी या तो गठबंधन की सरकारें थीं अथवा दूसरे दलों के समर्थन पर टिकी अल्पमत की सरकारें थीं जो इन सरकारों में शामिल नहीं हुए।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

In this new phase, any government could be formed only with the participation or support of many regional parties. This applied to the National Front in 1989, the United Front in 1996 and 1997, the NDA in 1997, the **BJP-led coalition in 1998,** the NDA in 1999, the UPA in 2004 and 2009. However, this trend changed in 2014.

इस नए दौर में कोई सरकार क्षेत्रीय पार्टियों की साझदारी अथवा उनके समर्थन से ही बनायी जा सकती थी। यह बात 1989 के राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, 1996 और 1997 की संयुक्त मोर्चा सरकार, 1998 और 1999 की राजग, 2004 और 2009 की संप्रग सरकार पर समान रूप से लागू होती है। हालांकि, 2014 में यह प्रवृत्ति बदल गयी है।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

Let connect this us development with what we have learnt so far. The era of coalition governments may be seen as a long-term trend resulting from relatively silent changes that were taking place over the last few decades. We saw in Chapter Two that in earlier times, it was the Congress party itself a 'coalition' that was and different interests different social strata and groups. This gave rise to the term 'Congress system'.

आइए, अब तक जो हमने सीखा उसे इस बदलाव के साथ जोड़कर देखने की कोशिश करें। माना जा सकता है कि गठबंधन सरकारों का यग लंबे समय से जारी कुछ प्रवृत्तियों की परिणति है। पिछले कुछ दशकों से भारतीय समाज में गुपचुप बदलाव आ रहे थे और इन बदलावों ने जिन प्रवृत्तियों को जन्म दिया, वे भारतीय राजनीति को गठबंधन की सरकारों के यग की तरफ ले आयीं।दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था कि शुरुआती सालों में कांग्रेस खुद में ही एक गठबंधननुमा पार्टी थी। इसमें विभिन्न हित, सामाजिक समूह और वर्ग एक साथ रहते थे। इस परिघटना को 'कांग्रेस प्रणाली' कहा गया।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

We also saw in Chapter Five that, especially since the late 1960s, various sections had been leaving the Congress fold and forming separate political parties of their own. We also noted the rise of many regional parties in the period after 1977. While these developments weakened the Congress party, they did not enable any single party to replace the Congress.

पाँचवें अध्याय में हम यह बात पढ चुके हैं कि 1960 के दशक से विभिन्न समूह कांग्रेस पार्टी से अलग होने लगे और इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनायी। हम इस बात पर भी गौर कर चुके हैं कि 1977 के बाद के सालों में कई क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ।इन सारे कारणों से कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हुई, लेकिन कोई दूसरी पार्टी इस तरह से नहीं उभर पायी कि कांग्रेस का विकल्प बन सके।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

Political Rise of Other Backward Classes One long-term development of this period was the rise of Other Backward Classes as a political force. You have already come across this term 'OBC'. This refers to the administrative category 'Other Backward Classes'.

अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय इस अवधि का एक दूरगामी बदलाव था—अन्य पिछड़ा वर्ग का उदय। आप 'ओबीसी' शब्द से परिचित होंगे। इससे विचार-विवेचन की एक प्रशासनिक कोटि 'अन्य पिछड़ा वर्ग' अथवा 'अदर बैकवर्ड क्लासेज्' का संकेत किया जाता है।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

These are communities other than SC and ST who suffer from educational and social backwardness. These are also referred to as 'backward castes'. We have already noted in **Chapter Six that the** support for the Congress among many sections of the 'backward castes' had declined.

यह अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से अलग एक कोटि है. जिसमें शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों की गणना की जाती है। इन समुदायों को 'पिछड़ा वर्ग' भी कहा जाता है। छठे अध्याय में हम यह देख चुके हैं कि पिछड़ी जातियों के अनेक तबके कांग्रेस से दूर जा रहे थे।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

This created a space for non-**Congress parties that drew** more support from these communities. You would recall that the rise of these parties first found political expression at the national level in the form of the Janata Party government in 1977. Many of the constituents of the Janata Party, like the Bharatiya Kranti and the Samyukta Dal Socialist Party, had a powerful rural base some among sections of the OBC.

उनमें कांग्रेस के लिए समर्थन कम होता जा रहा था। एसे में गैर-कांग्रेसी दलों के लिए एक जगह पैदा हुई और इन दलों ने इस तबके का समर्थन हासिल किया। आपको याद होगा कि गैर-कांग्रेसी दलों के राजनीतिक अभ्युदय की अभिव्यक्ति 1977 की जनता पार्टी की सरकार के रूप में हुई।जनता पार्टी के कई घटक मसलन भारतीय क्रांतिदल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का ग्रामीण इलाकों के अन्य पिछड़े वर्ग में ताकतवर जनाधार था।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

Mandal' implemented In the 1980s, the Janata Dal brought together a similar combination of political groups with strong support among the OBCs. The decision of the National Front government to implement the recommendations of the **Mandal Commission further** helped in shaping the politics of 'Other Backward Classes'.

'मंडल' का लागू होना 1980 के दशक में अन्य पिछड़ा वगों के बीच लोकप्रिय एसे ही राजनीतिक समूहों को जनता दल ने एकजुट किया। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया। इससे अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति को सुगठित रूप देने में मदद मिली।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

The intense national debate for and against reservation in jobs made people from the OBC communities more aware of this identity. Thus, it helped those who wanted to mobilise these groups politics. This period saw the emergence of many parties sought better that opportunities for OBCs in education and employment and also raised the question of the share of power enjoyed by the OBCs.

नौकरी में आरक्षण के सवाल पर तीखे वाद-विवाद हुए और इन विवादों से 'अन्य पिछड़ा वर्ग' अपनी पहचान को लेकर ज्यादा सजग हुआ। जो इस तबके को लामबंद करना चाहते थे, उन्हें इसका फायदा हुआ। इस दौर में एसी अनेक पार्टियां आगे आयीं. जिन्होंने रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की माँग की। इन दलों ने सत्ता में 'अन्य पिछडा वर्ग' की हिस्सेदारी का सवाल भी उठाया।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

These parties claimed that since OBCs constituted a large segment of Indian society, it was only democratic that the OBCs should get adequate representation in administration and have their due share of political power.

इन दलों का कहना था कि भारतीय समाज में अन्य पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा है। इसे देखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग का शासन में समुचित प्रतिनिधित्व और सत्ता में समुचित मौजूदगी तय करना लोकतांत्रिक कदम होगा।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

The Mandal Commission

Reservations for the OBC were in existence in southern States since the 1960s, if not earlier. But this policy was not operative in north Indian States. It was during the tenure of Janata Party government in 1977-79 that the demand for reservations for backward castes in north India and at the national level was strongly raised.

मंडल आयोग

दक्षिण के राज्यों में अगर बहुत पहले से नहीं तो भी कम-से-कम 1960 के दशक से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान चला आ रहा था। बहरहाल, यह नीति उत्तर भारत के राज्यों में लागू नहीं थी। 1977-79 की जनता पार्टी की सरकार के समय उत्तर भारत में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मज़बूती से आवाज़ उठाई गई।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

Karpoori Thakur, the then Chief Minister of Bihar, was a pioneer in this direction. His government had introduced a new policy of reservations for **OBCs in Bihar. Following** this, the central government appointed a Commission in 1978 to look into and recommend ways to improve the conditions of the backward classes.

बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्प्री ठाकुर इस दिशा में अग्रणी थे। उनकी सरकार ने बिहार में 'ओबीसी' को आरक्षण देने के लिए एक नयी नीति लागू की। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1978 में एक आयोग बैठाया। इसके जिम्मे पिछडा वर्ग की स्थिति को सुधारने के उपाय बताने का काम सौंपा गया।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

This was the second time since Independence that the government had appointed such a commission. Therefore, this commission was officially known as the Second **Backward Classes** Commission. Popularly, the commission is known as the Mandal Commission, after the name of its Chairperson, Bindeshwari **Prasad Mandal.**

आज़ादी के बाद से यह दूसरा अवसर था, जब सरकार ने एसा आयोग नियुक्त किया। इसी कारण आधिकारिक रूप से इस आयोग को 'दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग' कहा गया। आमतौर पर इस आयोग को इसके अध्यक्ष बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल के नाम पर 'मंडल कमीशन' कहा जाता है।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

The Mandal Commission was set up to investigate the extent of educational and social backwardness among various sections of Indian society and recommend ways of identifying these 'backward classes'. It was also expected to give its recommendations on the ways in which this backwardness could be ended.

मंडल आयोग का गठन भारतीय समाज के विभिन्न तबकों के बीच शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन की व्यापकता का पता लगाने और इन पिछड़े वगों की पहचान के तरीके बताने के लिए किया गया था। आयोग से यह भी अपेक्षा की गई थी कि वह इन वगों के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय सुझाएगा।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

The Commission gave its recommendations in 1980. By then the Janata government had fallen. The **Commission advised that** 'backward classes' should be understood to mean 'backward castes', since many castes, other than the Scheduled Castes, were also treated as low in the caste hierarchy.

आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें पेश कीं। इस वक्त तक जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी थी। आयोग का मशविरा था कि पिछड़ा वर्ग को पिछडी जाति के अर्थ में स्वीकार किया जाए, क्योंकि अनुसूचित जातियों से इतर एसी अनेक जातियां हैं. जिन्हें वर्ण व्यवस्था में 'नीच' समझा जाता है।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

The Commission did a survey and found that these backward castes had a very low presence in both educational institutions and in employment in public It therefore services. recommended reserving 27 per cent of seats in educational institutions and government jobs for these groups. The **Mandal** Commission also other made many recommendations, like, land the reform, to improve conditions of the OBCs.

आयोग ने एक सर्वेक्षण किया और पाया कि इन पिछडी जातियों की शिक्षा संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में बड़ी कम मौजूदगी है। इस वजह से आयोग ने इन समूहों के लिए शिक्षा संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत सीट आरक्षित करने की सिफारिश की।मंडल आयोग ने अन्य पिछडा वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए कई और समाधान सुझाए जिनमें भूमि-सुधार भी एक था।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

In August 1990, the National Front government decided to implement one of the recommendations of Mandal **Commission pertaining to** reservations for OBCs in jobs in the central government and its undertakings. This decision sparked agitations and violent protests in many cities of north India.

1990 के अगस्त में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों में से एक को लागू करने का फ़ैसला किया। यह सिफारिश केंद्रीय सरकार और उसके उपक्रमों की नौकरियों में अन्य पिछडा वर्ग को आरक्षण देने के संबंध में थी। सरकार के फैसले से उत्तर भारत के कई शहरों में हिंसक विरोध का स्वर उमडा।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

The decision was also challenged in the **Supreme Court and came** to be known as the 'Indira Sawhney case', after the name of one of the petitioners. In November 1992, the Supreme Court gave a ruling upholding the decision of the government.

इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई और यह प्रकरण 'इंदिरा साहनी केस' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सरकार के फ़ैसले के खिलाफ़ अदालत में जिन लोगों ने अर्जी दायर की थी, उनमें एक नाम इंदिरा साहनी का भी था। 1992 के नवंबर में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के निर्णय को सही ठहराते हुए अपना फैसला सुनाया।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

There were some differences among political parties about the manner of implementation of this decision. But now the policy of reservation for OBCs has support of all the major political parties of the country.

राजनीतिक दलों में इस फ़ैसले के क्रियान्वयन के तरीके को लेकर कुछ मतभेद था। बहरहाल अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मसले पर देश के सभी बड़े राजनीतिक दलों में सहमति थी।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

Political fallouts

The 1980s also saw the rise of political organisation of the Dalits. In 1978 the Backward and Minority Communities Employees Federation (BAMCEF) was formed. This organisation was not an ordinary trade union of government employees.

राजनीतिक परिणाम

1980 के दशक में दिलत जातियों के राजनीतिक संगठनों का भी उभार हुआ। 1978 में 'BAMCEF' (बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्पलाइज़ फेडरेशन) का गठन हुआ। यह सरकारी कर्मचारियों का कोई साधारण-सा ट्रेड य्नियन नहीं था।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

It took a strong position in favour of political power to the 'bahujan' - the SC, ST, OBC and minorities. was out of this that the subsequent Dalit Shoshit Samaj Sangharsh Samiti and later the Bahujan Samaj Party (BSP) emerged under the leadership of Kanshi Ram. The BSP began as a small party supported largely by Dalit voters in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. But in 1989 and the 1991 elections, achieved a breakthrough in Uttar Pradesh.

इस संगठन ने 'बहुजन' यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की जबरदस्त तरफदारी की। इसी का परवर्ती विकास 'दलित-शोषित समाज संघर्ष समिति' है, जिससे बाद के समय में बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ। इस पार्टी की अगुआई कांशीराम ने की।बहुजन समाज पार्टी (BSP) अपने शुरुआती दौर में एक छोटी पार्टी थी और इसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं का समर्थन हासिल था. लेकिन 1989 और 1991 के चुनावों में इस पार्टी को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

This was the first time in independent India that a political party supported mainly by Dalit voters had achieved this kind of political success.

आज़ाद भारत में यह पहला मौका था, जब कोई राजनीतिक दल मुख्यतया दलित मतदाताओं के समर्थन के बूते एसी राजनीतिक सफलता हासिल कर पाया था।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

In fact, the BSP, under Kanshi Ram's leadership was envisaged as an organisation based on pragmatic politics. It derived confidence from the fact that the Bahujans (SC, ST, OBC and religious minorities) cAonstituted the majority of the population, and were a formidable political force on the strength of their numbers.

दरअसल कांशीराम के नेतृत्व में बसपा ने अपने संगठन की बुनियाद व्यवहार केंद्रित नीतियों पर रखी थी। बहुजन (यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक) देश की आबादी में सबसे ज्यादा हैं और संख्या के लिहाज से एक मजबूत राजनीतिक ताकत का रूप ले सकते हें

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

Since then the BSP emerged as a major political player in the State and has been in government on more than one occasion. Its still strongest support comes from Dalit voters, but it has expanded its support now to various other social groups. In many parts of India, Dalit politics and OBC politics have developed independently and often in competition with each other.

BSP के आत्मविश्वास को इस तथ्य से बड़ा बल मिला था। इसके बाद बसपा राज्य में एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी और उसने एक से ज्यादा दफे यहां सरकार बनायी। इस पार्टी का सबसे ज्यादा समर्थन दलित मतदाता करते हैं. लेकिन अब इसने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अपना जनाधार बढ़ाना शुरू किया है।भारत के कई हिस्सों में दलित राजनीति और अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति ने स्वतंत्र रूप धारण किया है और इन दोनों के बीच अकसर प्रतिस्पर्धा भी चलती है।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

Communalism, Secularism, Democracy

The other long-term development during this period was the rise of politics based on religious identity, leading to a debate about secularism and democracy. We noted in **Chapter Six that in the** aftermath of the Emergency, the Bharatiya Jana Sangh had merged into the Janata Party.

सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र

इस दौर में आया एक दूरगामी बदलाव धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीति का उदय है। इसने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के बारे में बहसों को सरगर्म किया। हमने छठे अध्याय में पढा था कि आपातकाल के बाद भारतीय जनसंघ, जनता पार्टी में शामिल हो गया था।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

After the fall of the Janata Party and its break-up, the supporters of erstwhile Jana Sangh formed the **Bharatiya Janata Party (** BJP) in 1980. Initially, the **BJP** adopted a broader political platform than that of the Jana Sangh. It embraced 'Gandhian Socialism' as its ideology.

जनता पार्टी के पतन और बिखराव के बाद भूतपूर्व जनसंघ के समर्थकों ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बनाई। शुरू-शुरू में भाजपा ने जनसंघ की अपेक्षा कहीं ज्यादा बडा राजनीतिक मंच अपनाया। इसने 'गाँधीवादी समाजवाद' को अपनी विचारधारा के रूप में स्वीकार किया।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

But it did not get much success in the elections held in 1980 and 1984. After 1986, the party began to emphasise the Hindu nationalist element in its ideology. The BJP pursued the politics of 'Hindutva' and adopted the strategy of mobilising the Hindus.

बहरहाल भाजपा को 1980 और 1984 के चुनावों में खास सफलता नहीं मिली। 1986 के बाद इस पार्टी ने अपनी विचारधारा में हिंदू राष्ट्रवाद के तत्त्वों पर ज़ोर देना शुरू किया। भाजपा ने 'हिंदुत्व' की राजनीति का रास्ता चुना और हिंदुओं को लामबंद करने की रणनीति अपनायी।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

Hindutva literally means 'Hinduness' and was defined by its originator, V. D. Savarkar, as the basis of Indian (in his language also Hindu) nationhood. It basically meant that to be members of the Indian nation, everyone must not only accept India as their 'fatherland' (pitrubhu) but also as their holy land (punyabhu).

'हिंदुत्व' अथवा 'हिंदूपन' शब्द को वी.डी. सावरकर ने गढा था और इसको परिभाषित करते हुए उन्होंने इसे भारतीय (और उनके शब्दों में हिंदू) राष्ट की बुनियाद बताया। उनके कहने का आशय यह था कि भारत राष्ट का नागरिक वही हो सकता है, जो भारतभूमि को न सिर्फ 'पितृभूमि' बल्कि अपनी 'पुण्यभूमि' भी स्वीकार करे।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

Believers of 'Hindutva' argue that a strong nation can be built only on the basis of a strong and united national culture. They also believe that in the case of India the Hindu culture alone can provide this base

हिंदुत्व के समर्थकों का तर्क है कि मज़बूत राष्ट्र सिर्फ़ एकीकृत राष्ट्रीय संस्कृति की बुनियाद पर ही बनाया जा सकता है। वे यह भी मानते हैं कि भारत के संदर्भ में राष्ट्रीयता की बुनियाद केवल हिंदू संस्कृति ही हो सकती है।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

Two developments around 1986 became central to the politics of BJP as a 'Hindutva' party. The first was the Shah Bano case in 1985. In this case a 62-year old divorced Muslim woman, had filed a case for maintenance from her former husband. The Supreme Court ruled in her favour.

1986 में एसी दो बातें हुई, जो एक हिंदुवादी पार्टी के रूप में भाजपा की राजनीति के लिहाज से प्रधान हो गईं। इसमें पहली बात 1985 के शाहबानो मामले से जुड़ी है। यह मामला एक 62 वर्षीया तलाकश्दा मुस्लिम महिला शाहबानो का था। उसने अपने भूतपूर्व पति से गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए अदालत में अर्ज़ी दायर की थी।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

The orthodox Muslims saw the Supreme Court's order as an interference in Muslim Personal Law. On the demand of some Muslim leaders, the government passed the **Muslim Women (Protection** of Rights on Divorce) Act, 1986 that nullified the Supreme Court's judgment.

सर्वोच्च अदालत ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया। पुरातनपंथी मुसलमानों ने अदालत के इस फैसले को अपने 'पर्सनल ला' में हस्तक्षेप माना। कुछ मुस्लिम नेताओं की माँग पर सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम (1986) (तलाक से जुडे अधिकारों) पास किया। इस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले को निरस्त कर दिया गया।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

This action of the government was opposed by many women's organisations, many Muslim groups and most of the intellectuals. The BJP criticised this action of the Congress government as an unnecessary concession and 'appeasement' of the minority community

सरकार के इस कदम का कई महिला संगठनों, मुस्लिम महिलाओं की जमात तथा अधिकांश बुद्धिजीवियों ने विरोध किया। भाजपा ने कांग्रेस सरकार के इस कदम की आलोचना की और इसे अल्पसंख्यक समुदाय को दी गई अनावश्यक रियायत तथा 'तुष्टिकरण' करार दिया।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

Ayodhya dispute

The second development was the order by the Faizabad district court in February 1986. The court ordered that the Babri Masjid premises be unlocked so that Hindus could offer prayers at the site which they considered as a temple. A dispute had been going on for many decades over the mosque known as Babri Masjid at Ayodhya. The Babri Masjid was 16th century mosque Ayodhya and was built by Mir Baqi - Mughal emperor Babur's General.

अयोध्या विवाद

दूसरी बात का संबंध फैज़ाबाद ज़िला न्यायालय द्वारा फरवरी 1986 में सुनाए गए फ़ैसले से है। इस अदालत ने फ़ैसला सुनाया था कि बाबरी मस्ज़िद के अहाते का ताला खोल दिया जाना चाहिए, ताकि हिंदू यहां पुजा पाठ कर सकें, क्योंकि वे इस जगह को पवित्र मानते हैं।अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को लेकर दशकों से विवाद चला आ रहा था। बाबरी मस्ज़िद का निर्माण अयोध्या में मीर बाकी ने करवाया था। यह मस्ज़िद 16वीं सदी में बनी थी। मीर बाकी मुगल शासक बाबर का सिपहसलार था।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

Some Hindus believe that it was built after demolishing a temple for Lord Rama in what is believed to be his birthplace. The dispute took the form of a court case and has continued for many decades. In the late 1940s the mosque was locked up as the matter was with the court.

कुछ हिंदू मानते हैं कि भगवान राम की जन्मभूमि पर बने हुए एक राम मंदिर को तोड़कर उसी जगह पर यह मस्जिद बनवाई गई थी। इस विवाद नेअदालती मुकदमे का रूप ले लिया और मुकदमा कई दशकों तक जारी रहा। 1940 के दशक के आखिरी सालों में मस्जिद में ताला लगा दिया गया, क्योंकि मामला अदालत के हवाले था।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

As soon as the locks of the Babri Masjid were opened, mobilisation began on both sides. Many Hindu and Muslim organisations tried to mobilise their communities on this question. Suddenly this local dispute became a major national question and led to communal tensions.

जैसे ही बाबरी मिस्ज़िद के अहाते का ताला खुला, वैसे ही दोनों पक्षों में लामबंदी होने लगी। अनेक हिंदू और मुस्लिम संगठन इस मसले पर अपने-अपने समुदाय को लामबंद करने की कोशिश में जुट गए। भाजपा ने इसे अपना बहुत बड़ा चुनावी और राजनीतिक मुद्दा बनाया।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

This large scale mobilisation led to surcharged atmosphere and many instances of communal violence. The BJP, in order to generate public support, took out a massive march called the Rathyatra from Somnath in Gujarat to Ayodhya in UP.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद् जैसे कुछ संगठनों के साथ भाजपा ने लगातार प्रतीकात्मक और लामबंदी के कार्यक्रम चलाए। उसने जनसमर्थन जुटाने के लिए गुजरात स्थित सोमनाथ से उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या तक एक बड़ी 'रथयात्रा' निकाली।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

Demolition and after

In December 1992, the organisations supporting the construction of the temple had organised a Karseva, meaning voluntary service by the devotees, for building the Ram temple. The situation had become tense all over the country and especially at Ayodhya.

विध्वंस और उसके बाद

जो संगठन राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे थे. उन्होंने 1992 के दिसंबर में एक 'कारसेवा' का आयोजन किया। इसके अंतर्गत 'रामभक्तों' से आह्वान किया गया कि वे 'राम मंदिर' के निर्माण में श्रमदान करें। पूरे देश में माहौल तनावपूर्ण हो गया। अयोध्या में यह तनाव अपने चरम पर था।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

The Supreme Court had ordered the State government to take care that the disputed site will not be endangered. However, thousands of people gathered from all over the country at Ayodhya on 6 December 1992 demolished the mosque. news led to clashes between the Hindus and Muslims in many parts of the country. The violence in Mumbai erupted again in January 1993 and continued for over two weeks.

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह 'विवादित स्थल' की सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम करे। बहरहाल 6 दिसंबर 1992 को देश के विभिन्न भागों से लोग आ जुटे और इन लोगों ने मस्जिद को गिरा दिया।मस्जिद के विध्वंस की खबर से देश के कई भागों में हिंदू और मुसलमानों के बीच झड़प हुई। 1993 के जनवरी में एक बार फिर मुंबई में हिंसा भड़की और अगले दो हफ्तों तक जारी रही।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

The events at Ayodhya led to a series of other developments. The State government, with the BJP as the ruling party, was dismissed by the Centre. Along with that, other States where the BJP was in power, were also put under President's rule.

अयोध्या की घटना से कई बदलाव आए। उत्तर प्रदेश में सत्तासीन भाजपा की राज्य सरकार को केंद्र ने बर्खास्त कर दिया। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी, जहां भाजपा की सरकार थी, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

A case against the Chief Minister of Uttar Pradesh was registered in the Supreme Court for contempt of court since he had given undertaking that the disputed structure will be protected. The BJP officially expressed regret over the happenings at Ayodhya. The central government appointed a commission to investigate into the circumstances leading to the demolition of the mosque. Most political parties condemned the demolition and declared that this against the principles of secularism.

चूँकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात का हलफनामा दिया था कि 'विवादित ढाँचे' की रक्षा की जाएगी। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा दायर हुआ। भाजपा ने आधिकारिक तौर पर अयोध्या की घटना पर अफ़सोस जताया।केंद्र सरकार ने एक जाँच आयोग नियुक्त किया और उसे उन स्थितियों की जाँच करने के लिए कहा. जिनकी परिणति मस्ज़िद के विध्वंस के रूप में हुई थी। अधिकतर राजनीतिक दलों ने मस्ज़िद के विध्वंस की निंदा की और इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

This led to a serious debate over secularism and posed the kind of questions our country faced immediately after Partition - was India going to be a country where the majority religious community dominated over the minorities? Or would India continue to offer equal protection of law and equal citizenship rights to all Indians irrespective of their religion?

एसे में धर्मनिरपेक्षता पर गंभीर बहस चल पड़ी और हमारे सामने कुछ-कुछ वैसे ही सवाल आन खड़े हुए जैसे देश के बँटवारे के तुरंत बाद उभरे थे। बँटवारे के समय देश के सामने सवाल था: क्या भारत एक एसा देश बनने जा रहा है, जहां बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय का अल्पसंख्यकों पर दबदबा कायम होगा या व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो भारत में उसे समान रूप से कानून की सुरक्षा तथा बराबरी के नागरिक अधिकार दिए जाएँगे? बाबरी मस्ज़िद के ध्वंस के बाद भी देश में यही सवाल एक बार फिर-से मुखर हो उठे।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

During this time, there has also been a debate about using religious sentiments for electoral purposes. India's democratic politics is based on the premise that all religious communities enjoy the freedom that they may join any party and that there will not be communitybased political parties.

इसी अवधि में चुनावी उद्देश्य के लिए धार्मिक भावनाओं के इस्तेमाल पर भी बहस छिडी। भारत की लोकतांत्रिक राजनीति इस वायदे पर आधारित है कि सभी धार्मिक समुदाय किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल धार्मिक समुदाय पर आधारित दल नहीं होगा।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

This democratic atmosphere of communal amity has faced many challenges since 1984. As we have read in Chapter Eight, this happened in 1984 in the form of anti-Sikh riots. February-March 2002, similar violence broke out against the **Muslims** in Gujarat. Such violence against the minority community and violence between two communities is a threat to democracy.

सांप्रदायिक सौहार्द के इस लोकतांत्रिक माहौल को 1984 के बाद से कई दफा चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हम आठवें अध्याय में पढ चुके हैं कि एसा 1984 के सिख-विरोधी दंगों में हुआ। ठीक इसी तरह 2002 के फरवरी-मार्च में गुजरात के मुसलमानों के विरुद्ध हिंसा भड़की।अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ़ एसी हिंसा और दो समुदायों के बीच हिंसक टकराव लोकतंत्र के ऊपर खतरा है।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

Gujarat riots

In February-March 2002, large-scale violence took place in Gujarat. The immediate provocation for this violence was an incident that took place at a station called Godhra. A bogey of a train that was returning from Ayodhya and was full of Karsevaks was set on fire.

गुजरात के दंगे

2002 के फरवरी-मार्च में गुजरात में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। गोधरा स्टेशन पर घटी एक घटना इस हिंसा का तात्कालिक उकसावा साबित हुई। अयोध्या की ओर से आ रही एक ट्रेन की बोगी कारसेवकों से भरी हुई थी और इसमें आग लग गई। सत्तावन व्यक्ति इस आग में मर गए।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

Fifty seven people died in that fire. Suspecting the hand of the Muslims in setting fire to the bogey, large-scale violence against Muslims began in many parts of Gujarat from the next day. This violence continued for almost a whole month. Nearly 1100 persons, mostly Muslims, were killed in this violence.

यह संदेह करके कि बोगी में आग मुसलमानों ने लगायी होगी। अगले दिन गुजरात के कई भागों में मुसलमानों के खिलाफ़ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। हिंसा का यह तांडव लगभग एक महीने तक जारी रहा। लगभग 1100 व्यक्ति, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे, इस हिंसा में मारे गए।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

The National Human Rights Commission criticised the Gujarat government's role in failing to control violence, provide relief to the victims and prosecute the perpetrators of this violence. The Election **Commission of India** ordered the assembly elections to be postponed.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हिंसा को रोकने, भुक्तभोगियों को राहत देने तथा हिंसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने में असफल रहने के आरोप लगाते हुए गुजरात सरकार की आलोचना की। भारत के चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा के चुनावों को रोकने का फैसला किया।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

As in the case of anti-Sikh riots of 1984, Gujarat riots show that the governmental machinery also becomes susceptible to sectarian passions. Instances, like in Gujarat, alert us to the dangers involved in using religious sentiments for political purposes. This poses a threat to democratic politics.

1984 के सिख-विरोधी दंगों के समान गुजरात के दंगों से भी यह जाहिर हुआ कि सरकारी मशीनरी सांप्रदायिक भावनाओं के आवेग में आ सकती है। गुजरात में घटी ये घटनाएँ हमें आगाह करती हैं कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काना खतरनाक हो सकता है। इससे हमारी लोकतांत्रिक राजनीति को खतरा पैदा हो सकता है।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

Emergence ' a new consensus The period after 1989 is seen sometimes as the period of decline of Congress and rise of BJP. If you want to understand the complex nature of political competition in this period, you have to compare the electoral performances of the Congress and the BJP.

एक नयी सहमति का उदय 1989 के बाद की अवधि को कभी-कभार कांग्रेस के पतन और भाजपा के अभ्युदय की भी अवधि कहा जाता है। यदि आप इस दौर की राजनीति के जटिल चरित्र को समझना चाहते हैं. तो आपको कांग्रेस और भाजपा की चुनावी हार-जीत की तुलना करनी पड़ेगी।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

Lok Sabha Elections 2004

In the elections of 2004, the Congress party too entered into coalitions in a big way. The NDA was defeated and a new coalition government led by the Congress, known as the United Progressive Alliance came to power. This government received support from the Left Front parties.

2004 के लोकसभा चुनाव

2004 के चुनावों में कांग्रेस भी पूरे जोर के साथ गठबंधन में शामिल हुई। राजग की हार हुई और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की सरकार बनी। इस गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस ने किया। संप्रग को वाम मोर्चा ने समर्थन दिया।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

The elections of 2004 also witnessed the partial revival of Congress party. It could increase its seats for the first time since 1991. However, in the 2004 elections, there was a negligible difference between the votes polled by the Congress and its allies and the BJP and its allies. Thus, the party system has now changed almost dramatically from what it was till the seventies.

2004 के चुनावों में एक हद तक कांग्रेस का पुनरुत्थान भी हुआ। 1991 के बाद इस दफा पार्टी की सीटों की संख्या एक बार फिर बढ़ो।बहरहाल, 2004 के चुनावों में राजग और संप्रग को मिले कुल वोटों का अंतर बड़ा कम था। इस तरह दलीय प्रणाली सत्तर के दशक की तुलना में एकदम ही बदल गई है।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

The political processes that are unfolding around us after the 1990s show the emergence of broadly four groups of parties parties that are in coalition with the Congress; parties that are in alliance with the BJP; Left Front parties; and other parties who are not part of any of these three. The situation suggests that political competition will be multi-cornered. By implication the situation also assumes a of political divergence ideologies.

1990 के दशक के बाद से हमारे सामने जो राजनीतिक प्रक्रिया आकार ले रही है. उसमें हम मुख्य रूप से चार तरह की पार्टियों के उभार को पढ़ सकते हैं : कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल दल: भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल दल; वाम मोर्चा के दल और कुछ एसे दल जो इन तीनों में से किसी में शामिल नहीं हैं। इस स्थिति से संकेत मिलते हैं कि राजनीतिक मुकाबला बहुकोणीय होगा। इन स्थितियों का एक तकाजा राजनीतिक विचारधाराओं में हेर-फेर भी है।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

Growing consensus

However, on many crucial issues, a broad agreement has emerged among most parties. In the midst of severe competition and many conflicts, a consensus appears to have emerged among most parties. This consensus consists of four elements.

बढ्ती सहमति

बहरहाल, अनेक महत्त्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच एक व्यापक सहमित है। कड़े मुकाबले और बहुत-से संघषों के बावजूद अधिकतर दलों के बीच एक सहमित उभरती सी जान पड रही है। इस सहमित में चार बातें हैं।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

First, agreement on new economic policies - while many groups are opposed to the new economic policies, most political parties are in support of the new economic policies. Most parties believe that these policies would lead the country to prosperity and a status of economic power in the world.

पहला, नयी आर्थिक नीति पर सहमित : कई समूह नयी आर्थिक नीति के खिलाफ़ हैं, लेकिन ज्यादातर राजनीतिक दल इन नीतियों के पक्ष में हैं। अधिकतर दलों का मानना है कि नई आर्थिक नीतियों से देश समृद्ध होगा और भारत, विश्व की एक आर्थिक शिक्त बनेगा।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

Second, acceptance of the political and social claims of the backward castes - political parties have recognised that the social and political claims of the backward castes need to be accepted. As a result, all political parties now support reservation of seats for the **'backward** classes' education and employment. Political parties are also willing to ensure that the OBCs get adequate share of power.

दूसरा, पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति: राजनीतिक दलों ने पहचान लिया है। कि पिछडी जातियों के सामाजिक और राजनीतिक दावे को स्वीकार करने की ज़रूरत है। इस कारण आज सभी राजनीतिक दल शिक्षा और रोज़गार में पिछडी जातियों के लिए सीटों के आरक्षण के पक्ष में हैं। राजनीतिक दल यह भी सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं कि 'अन्य पिछडा वर्ग' को सत्ता में समुचित हिस्सेदारी मिले।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

Third, acceptance of the role of State level parties in governance of the country the distinction between State level and national level parties is fast becoming less important. As we saw in this chapter, State level parties are sharing power at the national level and have played a central role in the country's politics of last twenty years or so.

तीसरा, देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति: प्रांतीय दल और राष्ट्रीय दल का भेद अब लगातार कम होता जा रहा है। हमने इस अध्याय में देखा कि प्रांतीय दल केंद्रीय सरकार में साझोदार बन रहे हैं और इन दलों ने पिछले बीस सालों में देश की राजनीति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

Fourth, emphasis on pragmatic considerations rather than ideological positions and political alliances without ideological agreement coalition politics has shifted the focus of political parties from ideological differences to power sharing arrangements. Thus, most parties of the NDA did not agree with the 'Hindutva' ideology of the BJP. Yet, they came together to form a government and remained in power for a full term.

चौथा. विचारधारा की जगह कार्यसिद्धि पर जोर और विचारधारागत सहमति के बगैर राजनीतिक गठजोड : गठबंधन की राजनीति के इस दौर में राजनीतिक दल विचारधारागत अंतर की जगह सत्ता में हिस्सेदारी की बातों पर ज़ोर दे रहे हैं. जो मिसाल के लिए अधिकतर दल भाजपा की 'हिंदुत्व' की विचारधारा से सहमत नहीं हैं. लेकिन ये दल भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हुए और सरकार बनाई. जो पाँच साल तक चली।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

All these are momentous changes and are going to shape politics in the near future. We started this study of politics in India with the discussion of how the Congress emerged as a dominant party. From that situation, we have now arrived at a more competitive politics, but politics that is based on a certain implicit agreement among the main political actors.

ये सभी महत्त्वपूर्ण बदलाव हैं और आगामी राजनीति इन्हीं बदलावों के दायरे में आकार लेगी। भारत की राजनीति के इस अध्ययन की श्रुआत में हमने चर्चा की थी कि कांग्रेस किस तरह एक प्रभावशाली पार्टी बनकर उभरी। इस स्थिति से चलकर अब हम एक एसे पडाव पर पहुँचे हैं, जहां राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कहीं ज्यादा तेज़ है लेकिन इस प्रतिस्पर्धी राजनीति के बीच मुख्य राजनीतिक दलों में कुछेक मसलों पर सहमति है।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

Thus, even as political parties act within the sphere of this consenus, popular movements and organisations are simultaneously identifying new forms, visions and pathways of development. Issues like poverty, displacement, minimum wages, livelihood and social security are being put on the political agenda by peoples' movements, reminding the state of its responsibility.

अगर राजनीतिक दल इस सहमति के दायरे में सिक्रय हैं. तो जन आंदोलन और संगठन विकास के नए रूप. स्वप्न और तरीकों की पहचान कर रहे हैं। गरीबी, विस्थापन, न्यूनतम मज़दूरी, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा के मसले जन आंदोलनों के ज़रिए राजनीतिक एजेंडे के रूप में सामने आ रहे हैं। ये आंदोलन राज्य को उसकी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत कर रहे हैं।

भारतीय राजनीति : नए बदलाव

Similarly, issues of justice and democracy are being voiced by the people in terms of class, caste, gender and regions. We cannot predict the future of democracy. All we know is that democratic politics is here to stay in India and that it will unfold through a continuous churning of some of the factors mentioned in this chapter

इसी तरह लोग जाति, लिंग, वर्ग और क्षेत्र के संदर्भ में न्याय तथा लोकतंत्र के मुद्दे उठा रहे हैं। हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक राजनीति जारी रहेगी और यह राजनीति इस अध्याय में वर्णित कुछ चीजों के मंथन के बीच आकार ग्रहण करेगी।